Demand to take effective steps to control increasing population in the country

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, "Global Warming", "Climate Change", "Food Insecurity", आदि विश्वस्तरीय समस्या का कारण तो जनसंख्या वृद्धि है ही, लेकिन हमारे देश की हालत व्यापक रूप से गंभीर होने का मूल कारण भी जनसंख्या में व्यापाक बढ़ोत्तरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1949 को आधुनिक चीन का गठन हुआ। जनसंख्या पर ढंग से नियंत्रण करके कैसे वह देश दुनिया में तरक्की कर रहा है, यह सबको पता है। चीन तो दुनिया के राजनीति का ध्रुव बन गया है।

उससे दो साल पहले यानी 1947 को आधुनिक भारतीय संघ बनने के बावजूद हम हर मामले में बहुत पिछड़े हैं। यह बात अवश्य सत्य है कि जनसंख्या किसी राष्ट्र की ताकत होती है, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है। भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि इस मामले में अब वह चीन की जनसंख्या का भी अतिक्रमण कर जाएगा। केवल आबादी बढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। नौजवानों को रोजगार भी मुहैया कराना होगा। उन्हें कुशलतायुक्त भी करना होगा। लोगों को काम न मिलने से उनमें असंतोष बढ़ता है। बेरोजगार नौजवानों को गलत राह में लेने के लिए दुनिया में बहुत सारी भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। इनमें अतिवामवाद या नक्सलवाद प्रमुख हैं। लोगों की संख्या पिछले 62 सालों में इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए पीने का पानी तक उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। अतः शहरों या महानगरों में स्लमों की संख्या में व्यापक वृद्धि हो रही है।

इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देशों से आर्थिक दुरवस्था को बहाना बना कर यहां घुसपैठ हो रही है। ऐसा लगता है कि भारत की जनसंख्या को व्यापक रूप से बढ़ा कर इस देश का सर्वनाश कराने का षड्यंत्र कहीं-न-कहीं रचा जा रहा है। अतः सरकार इस बारे सचेत हों, ऐसी मेरी मांग है।

जनसंख्या नियंत्रण में धर्म या मज़हब का कोई बहाना न बनाया जाए। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई - इन सबको इस महान् कार्य हेतु प्रेरणा दी जाए और आवश्यकता पड़ने पर समान नागरिक कानून बनाया जाए। छोटा परिवार बनाने वालों को कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएं। सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने हेतु और उन्हें रोजगारयुक्त बनाने हेतु सुनियंत्रित जनसंख्या हमारा आज का ध्येय होना चाहिए।

Demand to give the special status to the State of Bihar

DR. C.P. THAKUR (Bihar): Sir, after separation of Jharkhand from the State of Bihar, Bihar was not left with any minerals or other resources with which to shape its economy. The State of Bihar abounds with land suitable for agriculture and people with intellect. But, 15 years of misrule resulted in the collapse of all infrastructure. As a result, Bihar became the poorest State in the country. In the light of the above-mentioned circumstances, such a big State with a huge population should not be allowed to continue in that state for long. On the one hand there is dismal poverty in Bihar and on the other hand, havoc created by floods in the Kosi and other Himalayan rivers has further aggravated the miseries of the people of that state. Therefore, it is high time that the Government gave Special Category State status to Bihar and provide special tax holiday schemes for industries. This would attract investments from industrialists into the State, thereby helping it to rebuild its financial capacity. It should not be regarded as a political stunt but a necessity for a big State with a huge population and extreme poverty. Once this stimulus is provided, the State would regain its lost glory.